भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद श्री राजनाथ सिंह द्वारा 17 जुलाई, 2009 को लोकसभा में दिये भाषण के प्रमुख अंश।

❖ मैडम स्पीकर, जब से देश को स्वतंत्रता मिली हैं और ससंद में देश की प्रगति के विषय में गंभीर चिंतन–मनन प्रारम्भ हुआ है तब से देश के नीति निर्माताओं ने सर्वाधिक चिंता कृषि और किसानों की ही की है।

– 1950 के दशक में ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट कह दिया था।

- 'Eveything else can wait but not Agriculture'

– इस वाक्य को दोहराया है और हर बार संकल्प लिया कि इस बार कृषि का कायाकल्प किया जायेगा।लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात।

❖ पिछले पचास साठ सालों में जो कृषि की दुर्दशा हुई है इस पर मात्र पचास–साठ मिनट के भाषण या एक दो बहस के आयोजन से काम नहीं चलने वाला। यदि सरकार कृषि के प्रति वाकई गम्भीर है तो वह कृषि की समस्याओं पर विचार करने के लिए और समस्याओं के समाधान पर विमर्श करने के लिए पन्द्रह दिनों या कम से कम दस दिनों का संसद का विशेष सत्र अलग से बुलाये।

– मैं आज सरकार पर दोषारोपण करने की मंशा से यहां नहीं खड़ा हुआ हूं बल्कि उन ज्वलंत

प्रश्नों की संसद में चर्चा करना चाहता हूं जिनका हल हर हाल में ढूंढना ही होगा।

– मैं मानता हूं कि भारत देश में यदि Agriculture fail कर गई तो विकास का हर Model देर–सवेर फेल हो जायेगा।

<u>कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न</u>

❖ भारत के पास सम्भवतः विश्व का सबसे बड़ा Research and Extension System है जिसमें ICAR System के अन्तर्गत लगभग 100 शोध संस्थान काम कर रहे हैं। फिर भी क्या कारण है कि भारत में अधिकांश फसलों की उत्पादकता उन फसलों की Global Average Productivity से कम है?

❖ संसार की लगभग हर फसल इस देश के किसी न किसी हिस्से में उगायी जाती है। फिर भी क्या कारण है कि हम अपनी इस विविधता और क्षमता का पूरा लाभ नहीं ले पाते और कृषि उत्पादों के कुल वैश्विक व्यापार में भारत से होने वाले निर्यात दो फीसदी से भी कम हैं?

❖ अपने विशाल Consumer base के कारण आज भारत खाद्य पदार्थों और कृषि से संबंधित विश्व की अधिकांश बड़ी कंपनियों के लिए favourite destination माना जाता है। इसके बावजूद कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण का स्तर 2 फीसदी के नीचे है।

- Food processing के लिए सरकार जो नाम मात्र का बजट आबंटित करती है।

उससे हमारी इस क्षेत्र के प्रति गंभीरता साफ पता चलती है।

– साथ ही यह भी पता चलता है कि सरकार किसानों को उनके उत्पादों के Value addition का लाभ नहीं देना चाहती और न ही उन्हें बाजार से सीधा जोड़ना चाहती है।

❖ तमाम तकनीकी विकास और Advanced Research के बावजूद भारत में अभी तक एक चौथाई फल एवं सब्जियां Waste हो जाती हैं जो पूरे ब्रिटेन द्वारा उपभोग किए जाने वाले फलों एवं सब्जियों की मात्रा से कहीं अधिक है।

❖ सरकार की लगातार कोशिश के बावजूद क्यों अभी तक आधी से अधिक कृषि आबादी बैंकों की पहुंच से बाहर है।

– हालत तो इतनी गम्भीर है कि पिछले तीन सालों में किसानों के बेंक खातों की संख्या जो पहले करीब चार करोड़ थी। वह अब घटकर 3 करोड़ 60 लाख ही रह गई है।

– मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हर किसान का बैंक खाता अनिवार्य से क्यों नहीं खोला जा सकता?

– इस देश में सभी किसानों का बैंक में खाता आसानी से और अनिवार्य रूप से खोला जाना चाहिए।

❖ जहां व्यापार के वैश्वीकरण और उदारीकरण के चलते हमारी किसान WTO के आगमन के पश्चात वैश्विक प्रतिस्पर्धा से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और बड़े पैमाने पर

Crop Shift Programme जैसे कामों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

- ❖ जहां इस देश में सिनेमा, खेल, खबर, फैशन अध्यात्म के लिए 300 से अधिक चैनल समर्पित हैं। कृषि के लिए एक भी चैनल नहीं है।
  - NDA सरकार ने 2004 में किसानों के लिए एक टेलीविजन चैनल प्रारम्भ किया था मगर तीन महीने में ही UPA सरकार ने चैनल बंद कर दिया।
  - मैं मांग करता हूं कि किसानों के लिए एक अलग से टीवी चैनल होना चाहिए जिससे कि कृषि की आधुनिक तकनीकि की जानकारी आम किसानों तक पहुंचे।

कृषि की वर्तमान स्थिति

- ❖ कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान 1950 की 55 फीसदी की तुलना में घट कर महज 17 फीसदी रह गया है। जबकि खेती पर निर्भर आबादी में कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की गई है।
  - कृषि क्षेत्र की औसत विकास दर पिछले साठ सालों में 2.5 फीसदी रही है।
- ❖ जहां कृषि का G.D.P. में योगदान लगभग 17 फीसदी का है। लेकिन कृषि एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए Plan Outlay महज 2 से 3 फीसदी तक ही सिमट गया है।

- ❖ पांचवी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने बुवाई किए गये कुल हेक्टेयर क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 63रूपये का खर्च किया गया। जबकि छठी योजना में 34 रूपये

प्रति हेक्टेयर का खर्च किया गया जबकि सातवीं योजना में यह खर्च मात्र 18 रूपये ही रह गया है।

- ❖ सरकार द्वारा कृषि के प्रति उपेक्षा के रवैये के कारण ही देश में कृषि के मामले में वह परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जो भारत की Inherent (इनहेरेंट) Strength के कारण होना चाहिए था।

- ❖ जब NDA की सरकार सत्ता में थी तो कृषि एवं अन्य सहयोगी क्षेत्रों में Gross Capital Formation की दर 11.7 फीसदी थी (2001–02)। NDA के शासन के दौरान अधिकांश समय कृषि में दस फीसदी GCF के आस–पास रही।

1999–2000	–	10.2%
2000–2001	–	9.7%
2001–2002	–	11.7%
2002–2003	–	10.3%
2003–2004	–	8.8%

- जबकि यूपीए सरकार के सत्ता में आते ही कृषि का GCF घट कर 7.7 प्रतिशत हो गया।
- उसके बाद हर बजट में सरकार के वित्त मंत्री कृषि की चिंता में दुबले होते मगर कृषि का G.C.F. में योगदान बढ़ने के बजाय घटने लगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि का G.C.F. में योगदान अभी भी 7 फीसदी से अधिक नहीं है।

❖ पिछले कुछ सालों में लगभग सभी प्रमुख जींसों के उत्पादन में कमी आई है। दाल का 2008–09 में कुल उत्पादन 14.18 मिलियन टन का रहा जो 2007–08 की तुलना में 3.9 फीसदी कम है। इसी तरह नौ तिलहन फसलों का या 2008–09 में कुल उत्पादन 281.3 लाख टन ही रहा जो 2007–08 की तुलना में 5.5 फीसदी कम रहा।

❖ जबकि गन्ने के उत्पादन में तो 2008–09 में 16.9 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है। 2007–08 में गन्ने का कुल उत्पादन 3482 लाख टन था जो 2008–09 में घटकर 2892 लाख टन ही रह गया।

❖ कपास का भी उत्पादन 10.1 फीसदी घटा है। 2007–08 में कपास का कुल उत्पादन 258.84 लाख गांठों का था जो 2008–09 में घटकर 232.68 लाख गांठ ही रहा गया है।

❖ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश को दूसरे ग्रीन रीवोल्यूशन की आवश्यकता है। उन्होंने इस बारे में देश की जनता को आश्वासन भी दिया कि 2015 तक देश में खाद्यान्न उत्पादन 200–230 मिलियन टन से बढ़ा कर दुगुना कर दिया जायेगा।
  – मगर सबसे अहम सवाल है कि हम इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे

❖ भारत को सिर्फ एक या दो ग्रीन रिवोल्यूशन की नहीं बल्कि एक एवरग्रीन रिवोल्यूशन की अधिक जरूरत है। इस इसके लिए उत्पादकता को सीधा बाजार और उपभोक्ताओं से जोड़ने की जरूरत है।

❖ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की गति काफी शिथिल है। 2005–06 से 2007–08 तक यानि तीन सालों

में कुल उत्पादन मात्र एक करोड़ टन बढ़ा है। जबकि लक्ष्य है 2015 तक कुल खाद्यान्न उत्पादन 40 करोड़ टन करने का।

❖ यदि सरकार तीन साल में 1 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन बढ़ायेगी तो 2015 तक हम मात्र 25 करोड़ तक ही पहुंच पायेंगे।

– 40 करोड़ टन तक पहुंचने में UPA सरकार को 45 साल लगेंगे।

– 2002–03 से 2007–08 तक देश की आवादी 8 फीसदी बढ़ी है। मगर खाद्यान्न उत्पादन में बमुश्किल 05 फीसदी की वृद्धि हुई है।

– सरकार को चाहिए था कि वह इस बजट में आवादी के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन में 3 प्रतिशत की शार्ट फाल को पूरा करने की योजना बनाती।

– इस शॉर्ट फॉल को पूरा करने के लिए सरकार ने किसी भी योजना का कोई उल्लेख नहीं किया है।

❖ उम्मीद थी कि सरकार को दुबारा अवसर मिला है इसलिए कम से कम इस बार खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कोई रोडमैप इस बार बजट में प्रस्तुत किया जायेगा। मगर आश्चर्यजनक से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के संदर्भ में कोई चर्चा तक नहीं की गई है।

❖ यदि सरकार कृषि के विकास के प्रति वाकई गम्भीर होती तो कृषि के लिए बजट आवंटन में नाम मात्र की वृद्धि नहीं की गई होती। 2009–2010 के बजट में कृषि के लिए 10629

करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई है जो पिछले बार की तुलना में मात्र 550 करोड़ अधिक है।

❖ कृषि के विकास के लिए बजट में कहा गया कि Credit Flow 2,87,000 करोड़ से बढ़ा कर 2009–10 में 3,25,000 करोड़ कर दिया जायेगा। मैं वित्तमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कृषि के लिए Credit availatity बढ़ाई है। लेकिन यह राशि मंहगी व्याज दर पर दी जायेगी।

❖ लेकिन वित्त मंत्री जी ने बड़ी होशयारी से जहां एक ओर कृषि के लिए Credit Flow बढ़ाने की बात की तो दूसरी तरफ Intrest Subvention के लिए जारी धनराशि घटा दी।वित्त मंत्री ने बजट में कहा।

-" To achives this, I propose to continue the interest subvention scheme for short-term crop loans to farmers for loans up to Rs three lakh per farmer at an interest rate of seven per cent per annum. I am also happy to announce that, for this year, the government shall pay an additional subvention (interest subsidy) of one percent as an incentive to those farmers who repay their short-term crop loans on schedule. Thus, the interest rates for these farmers wil

come down to six percent per annum. For this, I am making additional budget provisions of Rs 411 crore over interim budget estimate."

- जबकि Expenditure Budget के पेज 16 पर स्पष्ट लिखा है कि Short term credit का Interest subvention 2008–09 के 2600 करोड़ की अपेक्षा 2009–10 मे 2011 करोड़ कर दिया गया है।

- इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि बजट में यदि एक तरफ से राहत देने की बात की गई है तो दूसरी तरफ इसकी भी पक्की व्यवस्था की गई है कि इसका लाभ कम ही लोग उठा सके।

- देश में बांटे गये कर्ज की राशि पिछले तीन सालों में तिगुनी हो गई मगर कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या घट गई। कर्ज लेने वाले अधिकांश किसान बड़े किसान हैं जबकि छोटे और मझोले किसानों तक संस्थागत कर्ज की पहुंच नहीं है। 80 फीसदी छोटे और मझोले किसान गैर संस्थागत स्रोतो से कर्ज लेते हैं।
- 2008 में 71,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई मगर इसका उपयोग किसानों को राहत देने से कहीं अधिक बैंकों की बैलेंसशीट को 'Bad Loans' से उबारने में अधिक हुआ।
- जिस तरह किसानों की Input Cost तेजी से बढ़ी है उसे ध्यान में रखते हुए किसानों को कृषि कार्यों के लिए दिए गये ऋण की ब्याजदर 4 फीसदी से अधिक नही होनी चाहिए।

– सूखे और बाढ़ की स्थिति में ब्याज की दर शून्य होनी चाहिए।

❖ ऐसा नहीं है कि सरकार इन बातों से परिचित नहीं है क्योंकि किसानों की आत्महत्याओं का जो दौर इस देश में चल रहा है, उसका मूलभूत कारण ऊंची व्याज दरों पर कृषि ऋणों की उपलब्धता है।

❖ किसानों की ऋण माफी तात्कालिक उपाय है दीर्घकालीन नही। यदि कृषि का कल्याण करना है तो योजना और उपाय दोनों दीर्घकालीन ही होने चाहिए।

<u>फसलों का बीमा</u>

❖ कम व्याजदर पर कृषि ऋण की चर्चा मैंने अभी की मगर उसके साथ Farm Income Insurance Scheme को लागू किया जाना भी उतना ही आवश्यक है ताकि किसानों की गारण्टीड Income सुनिश्चित की जा सके।

❖ वर्तमान समय में जो फसल बीमा योजना चल रही है उसका लाभ अभी तक देश के कम ही किसानों को मिल रहा है। मैं सरकार से इस संदर्भ में विस्तृत आंकड़े जानना चाहूंगा।

– साथ ही सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि मौसम और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के खतरे लगातार बढ़ने के बावजूद फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है।

– क्या वर्तमान फसल बीमा योजना को मोटर वाहन बीमा की तरह अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता? इस पर विचार होना चाहिए।

❖ जब मैं कृषि मंत्री था तो मैने एक अनोखी योजना बनाई थी, जिससे किसानों की आर्थिक सुरक्षा का चक्र मजबूत हो जाता। परन्तु इस योजना की प्रशंसा करने के बावजूद यू.पी.ए. सरकार ने इस ठण्डे बस्ते में डाल दिया।

❖ केन्द्र सरकार ने पिछले बजट में किसानों की ऋण माफी के लिए साठ हजार करोड़ रूपये आवंटित किये थे। मगर इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में उन किसानों को नहीं मिल सका था, जिन्होंने महाजनों से कर्ज लिया था।

– मुझे प्रसन्नता है कि इस बार बजट में इस तरफ भी ध्यान दिया गया है और मामले की विस्तृत जानकारी के लिए एक Task Force के गठन का प्रस्ताव रखा गया।

– लेकिन इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द अमल में लाते हुए Task Force को गठित करके Time Bound report प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

❖ शार्ट टर्म क्रेडिट के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड से काफी सहूलियत हो सकती है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि ऐसी योजनाओं से लाभ लेने वाले किसानों की संख्या तेजी से नहीं बढ़ रही है।

– क्या कहीं Implementation के स्तर पर कमी है? या कोई अन्य Procedural समस्यायें है?

– इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए और कमियों को तत्काल दूर किया जाना चाहिए

- इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखकर NDA सरकार ने राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया था जिसने 2006 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी मगर उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

- यहां तक कि बजट में राष्ट्रीय कृषक आयोग की एक भी सिफारिश पर निर्णय लेना तो दूर इस पर preliminary step तक नहीं लिया गया है। इसी से समझ में आता है कि यह सरकार कृषि के लिए कितनी गम्भीर है।

- सरकार ने चुनाव से पहले और अब बजट में कुछ चुनिंदा sectors को stimulate करने के लिए तीन stimulus packages के साथ–साथ अन्य राहत प्रदान की है। परन्तु जब हम कृषि की बात करते हैं तो न तो चुनाव के पहले और न ही चुनाव के बाद प्रस्तुत बजट में कृषि के लिए कोई stimulus दिया।

- जबकि देश के सभी भागों में कृषि की productivity and profitability बढ़ाने के लिए एक Integrated Agricultural packages की आवश्यकता है।

Soil health बनाये रखना आवश्यक

- जब NDA शासन में था तो उस समय इस समस्या की गम्भीरता को समझते हुये मिट्‌टी की उर्वरता बढ़ाने के संबंध में कुछ दीर्घकालीन योजनायें बनायी गयी थीं जिसमें किसानों को

Soil Health Card दिये जाने के साथ–साथ मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाओं का आधुनिकिरण किये जाने पर विशेष बल दिया गया था।

– बिना Soil constitution समझे किसानों द्वारा उर्वरक का प्रयोग करने से मिट्टी की उत्पादकता घटनी निश्चित है।

– इस संबंध में इस बजट में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता थी। मगर आश्चर्य है कि बजट में इस बारे में भी चुप्पी है।

❖ मिट्टी में Nutrient Value बनी रहे इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। साथ ही जिन इलाकों की मिट्टी में पोषक तत्व की कमी है। वहां तो Soil Enrichment पर विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।

<u>मानसून पर कृषि की निर्भरता</u>

❖ भारत के किसान की मानसून पर अति निर्भरता उसकी स्थिति को मौसम के हाल की तरह बनाती है। इस साल भी कमजोर मानसून की खबर आ रही है। मगर सरकार की अभी भी इस स्थिति से निपटने की कोई खास तैयारी नही है।

❖ जबकि होना तो यह चाहिए था कि अब तक सरकार की तरफ से सूखे की स्थिति से निपटाने के के लिए एक एक्शन प्लान पर अमल प्रारम्भ हो जाना चाहिए था।

<u>सिंचाई</u>

❖ मिट्टी के साथ सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया जाना भी खाद्यान्न उत्पादन के लिए बेहद आवश्यक है। आज भी हमारे देश की कृषि सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है।

- इस साल मानसून ने थोड़ी आनकानी क्या की कि पूरे कृषि मंत्रालय के हाथ पांव फूल गये है।
- मानसून पर भारतीय कृषि की अतिशय निर्भरता हमें संकट में डाल सकती है।
- जल का कुशल प्रबन्धन और उपयोग आज पानी की समस्या के युग में बहुत आवश्यक हो गया है।
- एक जल आन्दोलन शुरू किये जाने के साथ–साथ भूजल के दीर्घकालीन उपयोग के लिए नियम कानून बनाये जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- इस संदर्भ में राष्ट्रीय कृषक आयोग ने सरकार को Detailed recommedation दी है परन्तु सरकार ने उन सभी को लेकर चुप्पी साध रखी है।
- सरकारी आंकडे गवाह हैं कि पिछली योजनाओं में हजारों करोड़ रूपये खर्च होने के बावजूद net irrigated area में बमुश्किल वृद्धि दर्ज की गई है।

❖ देश में मौजूद विशाल Rainfed Area जहां अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का कहर टूटता रहता है। इसके लिए सरकार ने एक National Rainfed Area Authourity बनाई थी कि यह

संस्था इन इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए कल्याणकारी योजनायें बनायेंगी मगर जब परीक्षा की घड़ी आयी है तो National Rainfed Area Authourity कुछ भी कर पाने में अपने को असमर्थ पा रही है।

उर्वरकों की कमी

- सिंचाई के साथ उर्वरक की उपलब्धता भी उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। सरकार आज तक पिछले पांच वर्षों से इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर पाई है।

- यह आश्चर्य का विषय है कि यूरिया का कुल उत्पादन 2002–03 में 187.27 लाख टन था। जो 2008–09 में मात्र 191 लाख टन तक ही पहुंच पाया है।

  – जबकि DAP खाद का तो उत्पादन 2002–03 के 52.36 लाख टन की अपेक्षा घट कर 29.33 लाख टन ही रह गया है।

- यद्यपि सरकार यह दावा करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से किसानों को खाद की मंहगाई से बचाये रखा है।

  – लेकिन सच्चाई यह है कि इस बार बजट में सरकार ने फर्टिलाईजर सब्सिडी के मद में पिछले साल की तुलना में 25 हजार करोड़ की कमी कर दी है।

– मैं यह मांग करता हूं कि फर्टिलाईजर सब्सिडी में की गई कटौती वापस ली जाए।

बीज

❖ उत्तम बीज कृषि के विकास का मूल आधार है। धीरे–धीरे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विकसित किये गये महंगे बीज इस देश के किसानों पर हावी हो रहे हैं।
  – लेकिन सरकार अभी तक बीज अनुसंधान के लिए कोष बनाने के बारे में मौन है जिसके माध्यम से भारतीय कम्पनियां भी बीज का विकास कर सकें।
  – न ही सरकार ने बीज की आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई न तो Seed Bank बनाया है और न ही कोई Seed Regulatory Authority बनाई है जो यह सुनिश्चित करे कि बीज के व्यापार में शामिल बड़े खिलाड़ी कोई घपला तो नहीं कर रहे या फिर किसानों के साथ धोखा तो नहीं किया जा रहा है।
  – सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय बीज उद्योग विदेशी बीज कम्पनियों के मुकाबले कहीं कमजोर न पड़ने पाये।

किसानों को मिले उपज वाजिब दाम

❖ किसान को धरातल पर चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े वह अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिलने पर अपनी सारी पीड़ा भूल जाता है। दुर्भाग्यवश पिछले कई सालों से किसान को अपने पसीने की वाजिब कीमत भी नहीं मिल पा रही है।

❖ दावा किया जाता है कि किसानों को उनकी उपज वाजिब मूल्य मिले इसके लिए CACP की संस्तुतियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। परन्तु सच्चाई तो यह है कि न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय शायद ही कभी CACP की संस्तुति मानी जाती है।

– चाहे स्वामी नाथन कमेटी द्वारा किसानों को C2+50% फॉर्मूला हो या वाई. के. अलघ कमीशन द्वारा CACP को Statutory Status की बात हो MSP तय करने का स्थापित मापदण्ड नहीं है।

❖ जब मझोले किसानों को Crop diversification की एडवाइज दी जाये, तो उसे एम.एस.पी. का आश्वासन भी साथ में जोड़कर दिया जाना चाहिए।

अनाज भण्डारण की समस्या

❖ पिछले कुछ वर्षों से सरकार का Food management भी लड़खड़ा कर ध्वस्त हो गया है। एक समय था। NDA सरकार ने 640 लाख टन खाद्यान्न भण्डारण कर लिया था। और तभी काम के बदल अनाज जैसी जन कल्याणकारी योजनायें सफल साबित हुई। मगर यू.पी.ए. सरकार का Food grains का Managememt नाकाम साबित हुआ है।

❖ इस साल सूखे जैसी स्थिति बन रही है। क्योंकि मानसून ने अभी तक मेहरबानी नहीं की है। ऐसी परिस्थिति में हमें यदि यह पता चले की कि भण्डारण की खामियों के चलते हजारों टन अनाज

उचित रख रखाव के अभाव में सड़ जाता है तो स्थिति और भी गम्भीर बन जाती है।

- ❖ राज्यों द्वारा खाद्यान्न की खरीद करवाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। FCI के पास जगह ही नहीं है।
- ❖ FCI ने भी यह स्वीकार किया है कि पिछले तीन सालों में करीब 1 लाख 10 हजार टन गेहूं चावल खराब हो गया है।
- ❖ आशा थी कि इस बजट में Storage Facility बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। क्योंकि सरकार National Food Security के लिए 3 रूपये प्रतिकिलो की दर से 25 किलो अनाज देने की योजना बना रही है।
- ❖ अनाज भण्डारण की कमी की समस्या से निपटने के लिए सरकार को पब्लिक प्राईवेट पार्टनर शिप में हर ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए।

<u>सार्वजनिक वितरण प्रणाली</u>

- ❖ चूँकि UPA सरकार Food Security बात करती है। इसलिए मैं उसे याद दिलाना चाहूंगा कि इस काम के लिए एक prompt delivery mechanism की आवश्यकता पड़ेगी।
- ❖ वर्तमान समय में जो PDS का delivery mechanism हैं वह काफी हद तक dysfunctional और भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। यदि गरीब और आम आदमी को सरकार

वाकई राहत पहुंचाना हैं तो उसे तत्काल अपना PDS मजबूत करना पड़ेगा।

❖ भारत मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या हालात है इस संबंध में एन.सी. सक्सेना समिति कहती है कि कुल गरीबों में से मात्र 49.1 प्रतिशत लोगों के पास बी.पी.एल. या अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड है।

– सक्सेना समिति यह भी बताती है कि 23 फीसदी गरीबों के पास कोई राशन कार्ड नहीं है।

– सक्सेना समिति यह भी बताती है कि 17.4 फीसदी बी.पी.एल. /अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड उन लोगों के पास भी हैं जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है।

– इसलिए National food security की दिशा में आगे बढ़ने से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

<u>Land Use Policy में सुधार की आवश्यकता।</u>

❖ देश में किसानों की लैण्ड होल्डिंगस छोटी है तथा बड़ी संख्या में लैण्डलेस Labourers मौजूद है।

❖ क्यों नहीं सरकार की तरफ से Work Land को Reclaim करने की कोई ऐसी पॉलिसी बनायी जाती है जिसमें भूमिहीन किसानों को भूमि विजरित की जाये ताकि उसका उपयोग कृषि के

Allied Sectors को मजबूत करने में किया जाये।

- ❖ Land Reforms का काम अभी अधूरा पड़ा है।
- ❖
  - – कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग पर पाबंदी लगनी चाहिए।
  - – पानी को साझा संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए।
  - – Land Leasing Act और Contract farming Act के provisions को Transparent Dynamic और Farmer friendly बनाया जाना चाहिए।

कृषि के क्षेत्र में चुनौतियां और अवसर

- ❖ Marginal और favoured areas में Productivity gap कम होना चाहिए और अगले दस वर्षों में सिंचित भूमि की उत्पादकता 35 फीसदी और असिंचित भूमि की उत्पादकता औसतन 50 फीसदी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

- ❖ पशुधन गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने, Farm Income बढ़ाने तथा ग्रामीण इलाकों में आजीविका बढ़ाने के बेहतर विकल्पों में से एक है। मगर वर्तमान बजट में सरकार ने इस बात की पूरी तरह उपेक्षा की है।

कृषि में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।

- ❖ भारत देश युवाओं का देश है और यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि बड़ी संख्या में देश के युवा

बेरोजगार हैं। इसके बावजूद युवाओं को रूझान कृषि की तरफ नहीं है।

- ❖ कृषि में अधिक संख्या में युवा आयें और जो युवक इस काम में लगे हैं वे पलायन न करें इसके लिए कृषि को intellectualy stimulating and economically rewarding बनाये जाने की आवश्यकता है।
- ❖ कृषि स्नातकों को हम क्यों नहीं Enterpreneur के रूप में विकसित करते हैं?

Extension Services में आई गिरावट

- ❖ तकनीक के क्षेत्र में मौजूद शिथिलता Extension Services में आई गिरावट को दूर करके तथा adequate quantity of quality inputs की supply सुनिश्चित करके देश में उत्पादकता को 150 से 200 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।
- ❖ आप सभी लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि उत्पादकता में आयी गिरावट को देखने के बावजूद भी Agriculture Research और Technology transfer के लिए Budgetary allocation में नाम मात्र की भी वृद्धि नहीं की गई है।

कृषि का भविष्य

- ❖ आज पूरे विश्व की निगाह कृषि क्षेत्र पर है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें Recession नहीं आता। Free market और Globalization के नाम पर Industry और Commerce के दरवाजे खोलने के बाद पश्चिमी देशों की निगाह भारत के विशाल Agriculture Sector पर लगी है।

- 2001 से WTO के माध्यम से कृषि सम्बन्धी मामलों में विकसित देश भारत जैसे विकासशील देशों की Arm twisting करने की कोशिश कर रहे हैं मगर अब तक उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है।

- जानकारी प्राप्त हुई है कि सितम्बर में भारत की राजधानी दिल्ली में ही प्रमुख देशों के वाणिज्य मंत्रियों को बुलाकर एक बैठक करके कुछ नरमी दिखाने की तैयारी की जा रही है।

- मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर एक भी कदम आगे बढ़ाने से पहले प्रतिपक्ष को भी विश्वास में लेना जरूरी है। इस देश का किसान ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। जिसमें उसका उसकी कृषि से नियंत्रण ही खो जाये।

- भारत का किसान स्वावलम्बी बने इसके लिए सरकार को एक Integrated Action plan बनाना चाहिए।

- कृषि के वैश्वीकरण की सम्भावनायें भारत के WTO के सदस्य होने के कारण के कारण लगातार बलवती हो रही है। और इस परिवर्तित माहौल में भारत किसान के अपने को काफी पिछड़ा महसूस करेगा। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी नीतियों को नई धार और नई दिशा देनी होगी।

- चूंकि फसलों की जैसी विविधता भारत में है। वैसी किसी देश के पास नहीं है इसलिए हमें Crop Planning के साथ –साथ किसानों को

Incentive देकर उन फसलों की तरफ प्रेरित करना होगा जिनमें भारत की अच्छी संभावनायें हैं।

- ❖ दुनियां में कृषि का भविष्य उज्जवल देखा जा रहा है। और नये–नये प्रयोग आजमाये जा रहे है। अमरीका में स्थित अमरीकन सोसायटी ऑफ एग्रोनामी के अनुसार भविष्य में Agriculture और allied sector एक होकर Agroforestry के रूप में जाने जायेंगे। Agroforestry में पेड़, पौधों के साथ तथा पशुधन का एक ऐसा balanced system तैयार होगा जो Biodirvesity के साथ–साथ Ecosystem को भी replenish (नई ऊर्जा से भर देगा) कर देगा।

- ❖ पश्चिमी देशों में तो Agriculture की तस्वीर बदलने की तैयारी जोरों पर है। परन्तु भारत में कृषि अभी भी उपेक्षित ही है। इस बार का बजट कृषि के मामले में पूरी तरह निराशाजनक साबित हुआ है। यह निराशा और भी दुखद है क्योकि सरकार ने अपने आर्थिक सर्वे में कृषि क्षेत्र की कई समस्याओं को स्वीकार किया है। परन्तु उनका समाधान ढूढ़ने की बजट में कोई गम्भीर कोशिश नहीं की गई।

- ❖ कृषि के बारे में सरकार को अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है। उसे कृषि को उद्योग के समकक्ष बल्कि उससे भी अधिक वरीयता देनी चाहिए। क्योंकि कृषि में आया सुधार देश की दो तिहाई आवादी के जीवन को सीधा प्रभावित करता है।